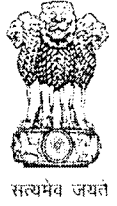




:: आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ::  
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एम टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan  
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road  
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

|   |   |                             |                  |
|---|---|-----------------------------|------------------|
| क | अपील / फाइलसंख्या/<br>Appeal / File No. | मूल आदेश सं /<br>O.I.O. No. | दिनांक/<br>Date: |
|   | V2/176/BVR/2018-19                      | 12/Excise/Demand/2018-19    | 29/6/2018        |

ख अपीलआदेशसंख्या(Order-In-Appeal No.):

**BHV-EXCUS-000-APP-221-2019**

|                                    |            |  |            |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| आदेश का दिनांक /<br>Date of Order: | 27.08.2019 | जारी करने की तारीख /<br>Date of issue: | 06.09.2019 |
|------------------------------------|------------|--|------------|

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /  
Passed by **Shri Gopi Nath**, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,  
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मुजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner,  
Central Excise/ST / GST, Rajkot/Jamnagar/Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellants & Respondent :-

**M/s.Kalpna Steel Works, Near Krishna Way Bridge, Old Bunder Road, Bhavnagar.**

इस आदेश (अपील) से न्यायित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारों / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) मीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/  
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन में सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/  
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतौर गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/  
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/  
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/  
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



(i) विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपील की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9 (2) एवं 9 (2A) के तहत निर्धारित फॉर्म ST-7 में की जानी चाहिए। अपील के साथ अपीलकर्ता केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रिय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें। (उनमें से प्रत्येक प्रतियाँ अपीलकर्ता के लिए और आयुक्त द्वारा महाशुल्क आयुक्त अथवा उत्पाद, केन्द्रिय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, की अपीलगी न्यायाधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत अपील के विषय में आदेश की प्रति की साथ में संलग्न करनी होंगी।)  
The appeal under sub section (2) and (2A) of Section 86 of the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST-7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise and Service Tax (copy of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Authority.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रिय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलगी न्यायाधिकरण (कार्य विधि) अधिनियम, 1982 के अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विन अधिनियम, 1994 की धारा 35एफ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलगी प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवाकर एवं मूल्य (मूल्य) (1994) एवं मूल्य एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस आदेश के अंतर्गत अपील के साथ अपील अधिनियम द्वारा गति वस्तु क्रोड रूप में अधिक न हो।  
केन्द्रिय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलगी न्यायाधिकरण (कार्य विधि) अधिनियम, 1982 में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (ii) मैनवेट जमा की गयी रकम
- (iii) मैनवेट जमा नियमावली के अधिनियम, 1982 के अंतर्गत रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के अंतर्गत अपील के लिए अधिनियम, 2014 के आरंभ में पूर्व किमी अपीलगी प्राधिकरण के समस्त विचारार्थन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT under Section 35E of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 86 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax (Duty Demanded) shall include:

- (i) amount determined under section 11 D
- (ii) amount of erroneous demand/ demand taken
- (iii) amount payable under Rules of the Central Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :  
**Revision application to Government of India**

इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर मन्त्रि, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, विस सेवाकर अधिकांश विभाग, सीईटी, अखिल दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए।  
A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Level 4, Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following cases, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किमी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किमी माल को किमी कारखाने के अंदर गृह के पारगमन के दौरान या किमी अन्य कारखाने या फिर किमी एक अंदर गृह से दूसरे अंदर गृह पारगमन के दौरान, या किमी अंदर गृह या अंदर गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किमी कारखाने या किमी अंदर गृह में माल के नुकसान के मामले में।  
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किमी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के निर्यात के अंतर्गत अवर मन्त्रि पर भरी गई केन्द्रिय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किमी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गई है।  
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है।  
In case of goods exported outside india export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो मन्त्रि के द्वारा इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विन अधिनियम (सं 2), 1994 की धारा 10S के अंतर्गत नियत की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।  
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की अपीलगी उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ इस आदेश व अपील आवेदन की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के अंतर्गत निर्धारित शुल्क की अदायगी के माध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।  
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

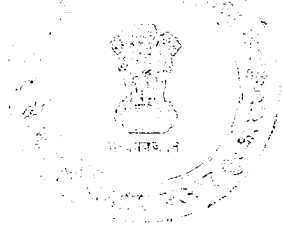
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।  
जहाँ मूल्य रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि मूल्य रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।  
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस न्यून के होते हुए भी की लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलगी न्यायाधिकरण को एक अपीलगी या केन्द्रिय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if existing Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।  
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रिय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलगी न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।  
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलगी प्राधिकरण को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यवस्था, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलगी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं।  
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in)



**:: ORDER IN APPEAL ::**

M/s Kalpana Steel Works, Old Bunder Road, Near Krishna Way Bridge, Bhavnagar, Pin - 364 001 (*hereinafter referred to as 'appellant'*) has filed the present appeal against Order-In-Original No. 12/Excise/Demand/18-19 dated 29.06.2018 (*hereinafter referred to as "impugned order"*) passed by the Assistant Commissioner, CGST Division Bhavnagar - I, Bhavnagar (*hereinafter referred to as "the adjudicating authority"*).

2. The brief facts of the case are that audit observed that appellant was availing benefit of Notification No. 08/2003-CE dated 01.03.2003 and paying central excise duty at the time of crossing threshold limit of Rs. 1.5 Crores with benefit of cenvat credit under Cenvat Credit Rules, 2004 (*hereinafter referred to as "the Rules"*); that the appellant has to pay amount equivalent to cenvat credit availed on the inputs which lying in stock as on 31<sup>st</sup> March during the period from 2010-11 to 2012-13; that it was observed from the balance sheet of the appellant that the appellant was required to reverse/pay the Cenvat credit contained in stock of goods on value declared in the balance sheet. Show Cause Notice bearing No. V/15-23/Demand-Kalpana/15-16 dated 04.11.2015 demanding total Cenvat credit/an amount equivalent to the Cenvat credit of Rs. 2,19,904/- under Section 11A of the Central Excise Act, 1944 (*hereinafter referred to as "the Act"*). The said SCN was decided by the adjudicating authority vide OIO No. 22/Demand/15-16 dated 09.03.2016 wherein demand of Rs. 1,05,815/- pertaining to the year 2010-11 and 2011-12 confirmed under Section 11A of the Act along with interest under Section 11AA of the Act and penalty of Rs. 1,05,815/- imposed under Rule 15(2) of the Rules read with Section 11AC of the Act and dropped the demand of Rs. 1,14,089/- pertaining to the period 2012-13. Being aggrieved with the said OIO, the appellant preferred appeal before the Commissioner (Appeals), Rajkot, who vide OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-003-2017-18 dated 27.04.2017 remand the matter back to the adjudicating authority. The adjudicating authority vide impugned order has confirmed the demand of Rs. 1,05,815/-.

3. Being aggrieved, the appellant has preferred the present appeal, *inter alia*, on the grounds that:

(i) The impugned order passed is bad in law, unjust and illegal; that they correctly and legally availed small-scale benefit under Notification No. 8/2003-CE;



*Alal*

that the adjudicating authority has wrongly considered the value of non-excisable goods while computing aggregate clearance value vide Notification No. 8/2003-CE; that actually sale value of the goods is nothing but value of charges of fabrication/repairing parts and machineries supplied by them to the customers; these charges are not considered by the adjudicating authority while deciding the issue.

(ii) The demand has been levied on the basis of the closing stock of value declared in the balance sheet for the year 2010-11 and 2011-12 and the adjudicating authority has not taken into account the value shown in the balance sheet is pertaining to the purchase of non-excisable goods only; that copies of invoices of non-excisable goods submitted by them during the course of deciding the issue; the adjudicating authority has passed the impugned order without taking into account the invoices of non-excisable goods purchased.

(iii) They vide their reply dated 10.02.2014 had proved that the value of the goods was of Rs. 8,70,300/- pertaining to the purchase of non-excisable goods only; that these goods were proved by producing purchase invoices; that the adjudicating authority has not denied that the appellant not fulfilled the conditions of the Notification No. 8/2003-CE read with the provisions of Rule 11(2) of the CCR; therefore, the department has accepted the lapsed/reversed central excise duty of Rs. 38,910/- pertaining to the financial year 2010-11; that the appellant has proved that the adjudicating authority again wrongly and without any justification has confirmed demand of Rs. 38,910/- pertaining to the said financial year.

(iv) They also proved that the amount of Rs. 17,114/- pertaining to the financial year 2011-12 was the amount pertaining to non excisable goods; that they have already paid the differential amount of Rs. 35,571/- along with interest amount of Rs. 16,898/- vide Cheque No. 120 dated 30.09.2014 to prove that they properly fulfilled conditions for SSI Exemption as provided under Rule 11(2) of the CCR; that the adjudicating authority has not accepted the said payment without any sustains to prove that the said payment was made in consultation with the range officer and it was declared in their reply dated 16.12.2015; that the adjudicating authority was required to get verified such information from the range officer and superintendent.

*Handwritten signature*



(v) That impugned order was passed without proper investigation of the case and without verification of central excise records viz. Daily Production Register, Register of receipt of Cenvatable inputs, ER-3 returns etc.; that the impugned order passed only on the basis of audit report; that balance sheet is not the exclusive evidence to prove the charged of demand in the present case; that no effective findings have been given by the adjudicating authority.

(vi) That the demand does not falls under the purview of Section 11A but covered under the provisions of Rule 11(2) read with Rule 14 of the Cenvat Credit Rules, 2004 and hence the matter has been decided beyond the facts and circumstances of the case.

(vii) That there was no suppression as much as department was aware that they were availing SSI exemption and an amount of Rs.50,757/- and Rs.39,034/- was lapsed on account of cenvat credit allowed in respect of inputs lying in stock etc. as on 31<sup>st</sup> March for the financial year 2010-11 and 2011-12 and also ER-3 returns were filed by them.

4. Personal hearing was granted to the appellant on 18.04.2019, however, the appellant vide letter dated 17.04.2019 has submitted written submission and requested to decide the appeal on the basis of grounds of appeal as well as written submission.

5 I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal and written submissions made by the appellant. The issue to be decided in the present appeal, in facts and circumstances of the case, is whether the appellant is liable to reverse amount, with reference to transitional provisions prescribed under Rule 11(2) of the CCR, equivalent to cenvat credit availed on inputs lying in stock as shown in the balance sheet and related documents/details or otherwise.

6. I find that, previously, this matter vide OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-003-2017-18 dated 27.04.2017 was remanded back to the adjudicating authority by the Commissioner (Appeals), Rajkot with specific directions to the adjudicating authority and the appellant. I would like to reproduce relevant Paras of the said OIA, which are reproduced as under:

"5.....I find that the adjudicating authority has observed that on verification of computer generated purchase register (party-wise) for the period 23.01.2011 to 31.03.2011 he find that it did not reflects any purchase of non-excisable goods. Whereas, countering that, the appellant produced a hand written copy of



*Handwritten signature*

*Hon'ble Commissioner (Appeals), Central Excise, Rajkot, therefore the submission made by them would not help them.*

6.2 The appellant contended that the adjudicating authority not considered the sale value of non-excisable goods and job work charges for fabrication work on damaged parts and machineries while confirming demand of Rs. 1,05,815/-. The appellant has submitted a hand written copy of purchase register of non-excisable goods along with copies of invoices with the appeal memorandum. However, it is not forthcoming from such documents that whether the stock of the goods lying as on 31<sup>st</sup> March of the respective year was non-excisable. I find that such purchase register and invoices don't serve purpose of proving purchase of non-excisable goods. I further find that the appellant failed to produce corroborative and conclusive documents to calculate and establish that they purchased non-excisable goods and the same were lying in stock as on 31<sup>st</sup> March of respective year. In such situation, I am of the considered view that the findings of the adjudicating authority are correct, proper and legal.

7. Accordingly, I uphold the impugned order and reject the appeal filed by the appellant.

6. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।  
8. The appeal filed by the Appellant is disposed off in above terms.

*General*  
6/9/19

*GOPI NATH*  
27/10/19  
Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To,  
M/s Kalpana Steel Works,  
Old Bunder Road,  
Near Krishna way bridge,  
Bhavnagar, Pin: 364 001.

मेसर्स कल्पना स्टील वर्क्स  
ओल्ड बंदर रोड  
कृष्णा वे ब्रिज के नजदीक  
भावनगर, पिन: ३६४ ००१.

प्रति:

- (1) प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- (2) आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर भावनगर - १, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(4) गार्ड फ़ाइल